दाल का प्रति व्यक्ति उत्पादन

9558. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1951 और 1 अप्रैल, 1978 को दाल का प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या था और इसी अवधि में प्रत्येक वार्षिक और पंचवर्षीय योजना के अन्त में यह उत्पादन कितना-कितना था ;

(ख) गत 30 वर्षों में दाल के प्रति व्यक्ति उत्पादन में कमी से प्रोटीन की जो कमी हुई है उसे पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार ने अधिक उत्पादन वाले दाल के बीजों को तैयार करने तथा और अधिक क्षेत्र में दाल की खेती करने के लिए कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और 1978-79 में दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1951-52 से वर्ष 1976-77 तक की अवधि के दौरान दाल का प्रति व्यक्ति उत्पादन विवरण में दिया गया है । वर्ष 1977-78 के उत्पादन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए है ।

(ख) दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले दालों से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य किए गए है । इन प्रयासों के फलस्वरूप मूंग (पूसा बैसाखी), उड़द (टी-9) तथा लोबिया (सी-152) की अल्पावधि किस्मों का विकास किया गया है । बहुफसली खेती के प्रतिमान के अन्तर्गत अन्तरवर्ती फसल, बीच की फसल अथवा मिश्रित फसल के रूप में दाल की जाती हैं । यह भी प्रमाणित हो चुका है कि दालों की खेती में राइजोबियल खेती तथा फास्फेटिक उर्वरकों के उपयोग से दालों की प्रति हैक्टार पैदावार में वृद्धि हो जाती है । कीट कृमियों के नियंत्रण के लिए वनस्पति रक्षण कार्यक्रम भी बनाये गये हैं । इसके अतिरिक्त, दालों की विभिन्न उन्नत किस्में, अर्थात् मूंग (टी-44, टी-2), उड़द (सलेक्शन 1), अरहर (टी-21, यू पी ए एस-120) मटर (टी-163), मसूर (एल 9-12, टी-36) और चना (सी-208) भी विकसित की गयी हैं, जिनकी खेती करने में उन्नत सस्य प्रणालियों को अपनाने से अधिक पैदावार होती है ।

अल्पावधि/उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने तथा उन्नत सस्य प्रणाली को अपनाने के लिए विकासोन्मुख प्रयास भी किए गए हैं ।

दालों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना भी 1972-73 में आरम्भ की गयी थी, जो अभी भी जारी है ।

उत्पादकों को दालो के अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए चने का साहाय मूल्य 95 रुपए प्रति क्विन्टल से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विन्टल कर दिया गया था ।

(ग) जी हां । सरकार ने सम्भाव्य क्षमता वाले राज्यों में मूंग की फसल के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग अभियान आरम्भ किया है और दालों की अल्पावधि तथा उन्नत किस्मों के बीजों के वर्धन के लिए भी कदम उठाए है । दालों के विकास से सम्बन्धित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्रजनन बीजों, आधारी बीजों तथा प्रमाणित बीजों के वर्धन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है । इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय महत्व की किस्मों के लिए दालों की

अच्छी किस्मों के बीजों के उत्पादन सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 के दौरान प्रजनक तथा आधारी बीजों के वर्धन के लिए निम्नलिखित दर से राज सहायता प्रदान की गयी थी :—

मद	राज सहायता
प्रजनक बीज उत्पादन	
मूंग, उड़द, लोबिया	500 रुपये प्रति क्विन्टल
मसूर	350 रुपये प्रति क्विन्टल
चना तथा अरहर	300 रुपये प्रति क्विन्टल
मटर	200 रुपये प्रति क्विन्टल
आधारी बीजों का उत्पादन	150 रुपये प्रति क्विन्टल

ये उपाय दाल की खेती के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने में सहायता करेंगे।

वर्ष 1978-79 में दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार निम्नलिखित उपाय कर रही है :—

(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को कृषकों के खेतों में प्रदर्शनों का आयोजन करने (ताकि उन्नत प्रणाली अपनाने के सम्बन्ध में उन्हें प्रेरित किया जा सके), अल्पावधि तथा उन्नत किस्मों के बीजों के वर्धन, राइजोबियल की खेती के अधिक उपयोग तथा दालों की खेती में वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(2) दालों से सम्बन्धित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय महत्व की दालों की अल्पावधि तथा उन्नत किस्मों के प्रजनक बीजों के वर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(3) राज्य सरकारों से कृषि / विकास विभागों के कर्मचारियों के संचालन द्वारा अभियानों के आयोजन के लिए अनुरोध किया जाएगा। इस अभियान में विस्तार कर्मचारियों (खरीफ में 9 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत रबी में भी समान संख्या के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) तथा कृषकों का प्रशिक्षण, उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों के उपयोग को प्रोत्साहन देना, फास्फेटिक उर्वरकों का उपयोग, राइजोबियल की खेती का अधिक उपयोग तथा वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाना शामिल है।

विवरण

वर्ष	प्रति वर्ष दालों का प्रति व्यक्ति उत्पादन किलोग्राम में
1951-52	24.7
1952-53	26.2
1953-54	29.1
1954-55	29 9
1955-56	29.5
1956-57	30.0
1957-58	24.4
1958-59	31.2
1959-60	27.4

वर्ष	प्रति वर्ष दालों का प्रति व्यक्ति उत्पादन किलोग्राम में
1960-61	28 8
1961-62	25 9
1962-63	25 0
1963-64	21 4
1964-65	25 7
1965-66	20 2
1966-67	16 6
1967-68	23 5
1968-69	19 9
1969-70	21 7
1970-71	21 4
1971-72	19 7
1972-73	17 2
1973-74	17 0
1974-75	16 7
1975-76	21 3
1976-77	17 9

टिप्पणी —दालो का प्रति व्यक्ति उत्पादन दालो के उत्पादन मे आबादी का भाग दे कर निकाला गया है । वर्ष 1951-52 मे 1964-65 तक के वर्षो के दौरान दालो के उत्पादन का अनुमान सूचकाको के आधार पर समायोजित किया गया है, जिनमे अनमानो के क्षेत्र तथा उनकी विधियो के परिवर्तन को भी ध्यान मे रखा गया है । आबादी के अनमान प्रति वर्ष की 1 जुलाई से सम्बन्धित है ।

राष्ट्रीय आवास नीति

9559. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाच वर्षों मे सरकार के विचाराधीन राष्ट्रीय आवास योजना को 31 मार्च, 1978 तक अन्तिम रूप न देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने नगर तथा ग्रामी ण क्षेत्रों की राज्यवार आवास आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक समिति की नियुक्ति की है और इस आवश्यकता को पूरा करने पर कितना व्यय होगा, यदि हा, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नही, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार को राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रों की अलग अलग आवास आवश्यकताओं की जानकारी है और क्या सरकार इसको पूरा करने के लिए किसी सम्बन्धित योजना पर विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) मूलत , आवास राज्य क्षेत्र का विषय है और केवल बागान कर्मचारियो की सहायता प्राप्त आवास योजना ही केन्द्रीय क्षेत्र में है । केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निधिया समेकित ऋणो तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती हैं और राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताएं स्वयं निर्धारित करने मे स्वतंत्र है , तथापि. आवास के क्षेत्र में भावी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(1) ऐसा आवास कार्यक्रम चलाना जिस का उद्देश्य 20 वर्ष की अवधि में पिछले बकाया को पूरा करना तथा जनसंख्या के बढ़ जाने के कारण